



आरत का राजपत्र | |

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राविकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. ५२२] नई विलासी, शुक्रवार, दि सम्ब ९, १९७७/ग्रहणाद्या १८, १८९९

No. ५२२] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 1977/AGRAHAYANA १८, १८९९

इस भाग में भिन्न पट संलग्न ही जारी है—जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION***New Delhi, the 9th December 1977*

S. O 828 (E).—The following Order made by the President published for general information:—

ORDER

Whereas the Vice-President acting as President had on 11th May, 1977 made an Order suspending for a period of seven months from that date the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), (hereinafter referred to as "the Act") in relation to the Union territory of Mizoram, and making certain incidental and consequential provisions which appeared to him to be necessary and expedient for administering the Union territory of Mizoram in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period;

And whereas I have received a report from the Administrator of the Union territory of Mizoram and after considering the report and other information received by me I am satisfied that the situation in the Union territory continues to be such that the administration of that territory cannot be carried on in accordance with the provisions of the Act and that for the proper administration of that

Union territory it is necessary that the operation of the provisions of the Act suspended under the said Order should continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made therein should continue to operate beyond the period of seven months aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and all other powers enabling me in that behalf, I Neelam Sanjiva Reddy, President of India hereby direct—

- (a) that the operation of the provisions of the Act suspended by virtue of clause (a) of the said Order shall continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made by virtue of clause (b) of the said Order shall continue to be operative for a further period of four months with effect from the 11th December, 1977, and
- (b) that for the words "seven months" occurring in clause (a) of the said Order, the words "eleven months" shall be substituted.

New Delhi;
The 9th December, 1977.

NEELAM SANJIVA REDDY,
President.

[No. U-11012/11/77-UTL]
M. L. KAMPANI, Jt. Secy.

गृह भौत्रालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1977

का० पा० 828 (भ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित भारत सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आवेदन

यतः राष्ट्रपति के कानून में काँटे काँटे हुए, उपरा द्रष्टि ने 11 मई, 1977 को एक भारत किया था निम्नों भिन्नों संबंधीय संघ राज्यसेवक के संवर्धन में संघ राज्यसेवक प्रशिनियम 1963 (1963 का 20) (जिसे इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है) के कठिपथ उपबन्धों का प्रवर्तन उत्तरार्द्ध से सात मास की अवधि के लिए निर्मित कर दिया था और जिसमें पूर्वोक्त अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबन्धों के अनुवरण में भिन्नों संघ राज्यसेवक के प्रशासन के सिए ऐसे कठिपथ आनुबंधिक और पारिणामिक उपबन्ध बनाए गए थे, जो उन्हें आवश्यक और समीक्षिक प्रतीत हुए;

ओर यतः मुझे भिन्नों संघ राज्यसेवक से एक स्पोर्ट प्राप्त हुई है और मुझे प्राप्त रिपोर्ट तथा ग्रा०-प जानकारी पर विचार करने के पश्चात मेरा यह समाधान हो गया है कि संघ राज्यसेवक में ऐसी स्थिति जारी है कि उत्तरार्द्ध का प्रशासन अविनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यद् कि मध्य राज्यसेवक के उचित प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि उक्त भारत के अधीन निर्मित किया गया अविनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन निर्मित बना रहना चाहिए और उसमें बनाए गए आनुबंधिक और पारिणामिक उपबन्ध पूर्वोक्त सात मास की अवधि के परे प्रवर्तित रहने चाहिए;

ग्रन्तः, ग्रन्त, मैं, नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति, अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त, शक्तियों और इस निमित्त भूमि समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश देखा द्वृं कि—

- (क) उक्त आदेश के खण्ड (क) के आधार पर निलम्बित किया गया अधिनियम के उपनियमों का प्रवर्तन निलम्बित बना रहेगा और उक्त आदेश के खण्ड (ख) के आधार पर बनाए गए आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध 11 दिसम्बर, 1977 से और चार मास की कालावधि के लिए प्रवृत्त बने रहेगे; और
- (ख) उक्त आदेश के खण्ड (क) में आने वाले “सात मास” शब्दों के स्थान पर “मार्यादा मास” शब्द रखे जाएंगे।

मई दिल्ली;

९ दिसम्बर, 1977

नीलम संजीव रेड्डी,

राष्ट्रपति।

[सं० य०-११०१२/११/७७-०टी०एस०]

म० ला० कल्पानी, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

